>

Title: Need to continue and extend tax-holiday scheme to industries in Himachal Pradesh till 2020.

***प्रो. प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर):** महोदय, मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश उच्च पर्वतीय शृंखलाओं में स्थित सीमावर्ती प्रांत है, जिसके कारण वहां आर्थिक गतिविधियां बहुत कम तथा कृषि कार्य न्यून है। जब से देश की सेना में भर्ती का आधार संबंधित प्रदेश की आबादी हुई है तब से हिमाचल प्रदेश से सेना में कम भर्ती होती है। इसलिए वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए एनडीए सरकार ने प्रदेश को 2002 में एक विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर आदि मदों की टैक्सों में वर्ष 2013 तक छूट दी है। इससे लघु उद्योगों के साथ-साथ एंसीलियरी उद्योग पनप रहे हैं। फलस्वरूप रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं।

महोदय, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेस में उद्योगों को दी गई छूट वापस लेने पर विचार कररही है। यदि ऐसा किया गया, तो वहां लघु तथा एंसीलियरी उद्योग बर्बाद हो जाएंगे और अंततः प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि यदि वह इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, तो उसे तत्काल प्रभाव से त्याग दे और उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों को वर्ष 2013 से और आगे 2020 तक बढ़ाए, ताकि प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो।

MR. SPEAKER: Shri G. Karunakara Reddy.

Shri Subhash S. Deshmukh.

Shri Mahavir Bhagora.

Dr. K.S. Manoj.

...(*Interruptions*)

---

* Treated as laid on the Table.